संपादकीय जागरण

रविवार, 29 अप्रैल, 2018 : वैशाख शुक्ल 14 वि. 2075

शांति और समृद्धि एक दूसरे के पर्याय हैं

हर गांव में बिजली

हर गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य में मिली सफलता मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के साथ ही मोदी सरकार अपने एक और वायदे को पूरा करने में सफल रही। खास बात यह है कि यह वायदा तय समय के पहले ही पूरा कर लिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने हर गांव में बिजली पहुंचाने की घोषणा सत्ता संभालने के कुछ दिन बाद 2015 में स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से की थी। उन्होंने इसके लिए एक हजार दिन मांगे थे। स्पष्ट है कि इस घोषणा को समय रहते पूरा करने के लिए केंद्रीय बिजली मंत्रालय के अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं। हर गांव में बिजली पहुंचाने के काम को इसलिए कम करके नहीं आंका जाना चाहिए कि एक हजार दिनों में करीब 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि इनमें से ज्यादातर गांव दुर्गम इलाकों में थे। कुछ गांव ऐसे भी थे जो नक्सलवाद की चपेट में थे और यह किसी से छिपा नहीं कि नक्सली किस तरह विकास की हर योजना के बैरी बन बैठे हैं। संसाधन विहीन गांवों में बिजली के रूप में विकास की रोशनी पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण काम था। यह चुनौती पूरी करने के साथ ही सरकार का काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसे हर घर तक बिजली पहुंचाने का भी काम करना है। यह हर गांव में बिजली पहुंचाने से कहीं अधिक कठिन काम है और इसमें सफलता तब मिलेगी जब राज्य सरकारें भी केंद्रीय बिजली मंत्रालय जैसी सक्रियता और सजगता का परिचय देंगी। राज्य सरकारों को हर घर तक बिजली पहुंचाने के मामले में इसलिए तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि आज बिजली विकास का पर्याय है। बिजली की उपलब्धता केवल अंधेरे घरों को जगमग ही नहीं करती, बल्कि वह आम लोगों की जीवनचर्या को कहीं अधिक सुविधाजनक भी बनाती है। इस सबके अतिरिक्त बिजली विकास का वाहक भी है।

हालांकि घर-घर बिजली पहुंचाने की योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन इस पर निगाह रखने की जरूरत बनी हुई है कि इस योजना का लाभ पात्र लोग ही उठाएं और बिजली चोरी पर लगाम लगे। इस सबके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर भी गौर करना होगा कि बिजली पंहुच जाने के बाद भी गांव अंधेरे में डूबे हुए नजर न आएं। इस क्रम में यह भी अपेक्षित है कि विपक्षी दल हर गांव में बिजली पहुंचाने की योजना के क्रियान्वयन में कोई कमी दिखने पर सरकार की खिल्ली उड़ाने के बजाय कमियों को दूर करने में सहायक बनें। निःसंदेह बिजली उत्पादन के मामले देश आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में है, लेकिन बिजली वितरण की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है। इसी तरह बिजली पहुंचाने में होने वाली बिजली हानि को भी कम करने की सख्त जरूरत है। इस जरूरत की पूर्ति इसलिए नहीं हो पा रही है, क्योंकि बिजली उपकरणों का रखरखाव उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है। यह ध्यान रहे तो बेहतर कि बिजली संयंत्रों के साथ बिजली उपकरणों के रखरखाव को दुरुस्त करके ही देश बिजली उपभोग के स्तर को सुधार सकता है।

मरीजों से अन्याय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल गंभीर मामला है। पिछले तीन दिनों तक चली हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वे इलाज के लिए भटकते रहे। इसलिए इसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। यह पहला मामला नहीं है जब एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में डॉक्टर हड़ताल पर गए हों। इससे पहले भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने और अन्य मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर चुके हैं। दिल्ली के अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों का भी यही हाल है। यह मरीजों के साथ अन्याय है। एम्स सहित अन्य अस्पतालों में न सिर्फ दिल्ली के बल्कि दूसरे राज्यों से भी मरीज बड़ी उम्मीद के साथ पहुंचते हैं। लंबे इंतजार के बाद उन्हें इलाज का नंबर मिलता है। दिल्ली में कोई ठिकाना नहीं होने और पैसे के अभाव में अधिकांश गरीब मरीज इलाज की उम्मीद में अस्पतालों के बाहर फुटपाथ पर समय गुजारते हैं, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से वे इलाज से वंचित रह जाते हैं।

एम्स सहित अन्य अस्पतालों में दूसरे राज्यों से भी मरीज उम्मीद के साथ पहुंचते हैं, हड़ताल से उन्हें निराशा हाथ लगती है

इसलिए डॉक्टरों को अपनी मांग मनवाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। मरीज का इलाज न करने का फैसला अनुचित है।

रेजिडेंट डॉक्टरों की चिंता और उनकी नाराजगी को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सुरक्षित माहौल में स्वाभिमान के साथ काम करना उनका अधिकार है। एक सीनियर द्वारा रेजिडेंट डॉक्टर पर हाथ उठाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए एम्स प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी डॉक्टर को पद से हटा दिया है। भविष्य में इस तरह की अप्रिय घटना दोबारा न हो इसके लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

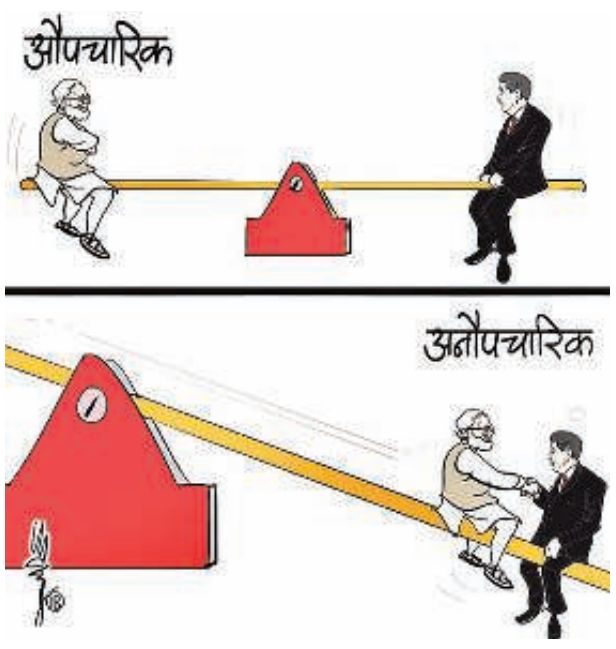

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या कुशीनगर हादसे के लिए ड्राइवर की लापरवाही से कहीं अधिक मानवरहित रेलवे फाटक जिम्मेदार है?

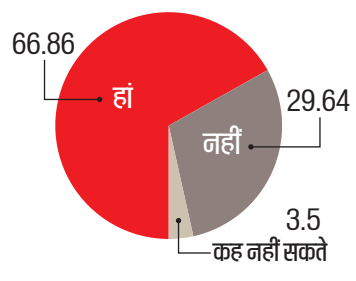

आज का सवाल

क्या प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे के बाद दोनों देशों के संबंधों में अपेक्षित सुधार होगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

वुहान ने जगाई एक उम्मीद

संजय गुप्त

मोदी और चिनफिंग के बीच बनी सहमति ने सीमा विवाद पर टकराव की आशंका को कम तो किया है, लेकिन अभी उसे पूरी तौर पर दूर करना शेष है

वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता में किसी समझौते की घोषणा न होने के बावजूद उसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए संचार तंत्र को मजबूत करने और आपसी समझ विकसित करने के लिए अपनी-अपनी सेनाओं को रणनीतिक मार्गदर्शन जारी करने का फैसला किया। इसके अलावा चीन ने संकेत दिए कि वह अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट-वन रोड में भारत की भागीदारी पर जोर नहीं देगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाला चीन निर्मित आर्थिक गलियारा इसी परियोजना का हिस्सा है। यह भी खासा उल्लेखनीय है कि दोनों देशों में अफगानिस्तान में मिलकर काम करने की समझबूझ बनी। बीते वर्ष डोकलाम में 73 दिनों के गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच इस तरह आपसी समझ कायम होना एक कूटनीतिक कामयाबी है। इस कामयाबी तक इसीलिए पहुंचा जा सका, क्योंकि डोकलाम विवाद के बाद दोनों देशों ने अपने-अपने स्तर पर संबंध सुधारने की पहल की और आखिरकार भारतीय प्रधानमंत्री जून में चीन के अपने प्रस्तावित दौरे के पहले ही चीनी राष्ट्रपति से मिलने वुहान गए। ऐसे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन दुर्लभ ही होते हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश ही नहीं, एशिया की एक ऐसी बड़ी ताकत है जो दुनिया में अपनी छाप छोड़ने को तत्पर है, लेकिन वह इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि भारत भी एक उभरती हुई ताकत और सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक पेचीदा मसला बना हुआ है। डोकलाम में टकराव इसी सीमा विवाद की उपज था। हालांकि 1962 के युद्ध के बाद चीन सीमाओं पर शांति बनाए हुए है, लेकिन उसकी आक्रामकता किसी से छिपी नहीं। भारत ने तिब्बत को चीन के स्वायत्तशासी क्षेत्र के रूप में मान्यता देकर यह समझा था कि इससे चीन अपने विस्तारवादी रवैये का परित्याग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल डोकलाम में भूटान के इलाके में सड़क निर्माण की चीन की कोशिश उसके विस्तारवादी रवैये के साथ ही इसका भी सूचक थी कि वह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इस खतरे को भांपकर ही भारत ने डोकलाम में अपनी सेनाएं भेजीं और चीन की तमाम धमकियों के बाद भी अपने कदम पीछे खींचने से इन्कार किया। भारत की दृढ़ता के आगे चीन को पीछे लौटना पड़ा। जब यह आशंका थी कि चीन फिर से डोकलाम अथवा अरुणाचल या लद्दाख में अतिक्रमण की कोशिश कर सकता है तब उसने अपना रुख नरम किया। इसके जवाब में भारत ने भी दलाई लामा को लेकर उसकी चिंताओं को समझा। इसके बाद दोनों देशों ने संबंध सुधार की जो कोशिश की उसका ही नतीजा वुहान में अनौपचारिक बैठक के रूप में देखने को मिला। वुहान में दोनों देशों के नेताओं ने भारत-चीन के प्राचीन संबंधों का स्मरण किया। चूंकि चीन में प्रचलित बौद्ध धर्म भारत की ही देन है इसलिए दोनों देशों के बीच एक आध्यात्मिक रिश्ता भी है। इस रिश्ते के बाद भी दोनों देशों के संबंधों में वैसी मधुरता नहीं जैसी होनी चाहिए। इसका मूल कारण पुराने समझौतों को नकारने की चीन की आदत है। वह अन्य किसी से अपने लिए जैसे आचरण की अपेक्षा करता है वैसा दूसरों के प्रति प्रदर्शित करने से इन्कार करता है।

अवधेश राजपूत

शी चिनफिंग के आजीवन राष्ट्रपति के तौर पर स्थापित होने के बाद यह माना गया था कि चीन के विस्तारवादी रुख में और आक्रामकता देखने को मिलेगी और इसके चलते सीमा विवाद सुलझाने में कहीं मुश्किल हो सकती है। इसमें दोराय नहीं कि वुहान में दोनों देशों के बीच विभिन्न मसलों पर बनी सहमति ने सीमा विवाद पर टकराव की आशंका को कम तो किया है, लेकिन अभी उसे पूरी तौर पर दूर करना शेष है। बावजूद इसके वुहान में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात के विरोध का कोई औचित्य नहीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुलाकात को लेकर कटाक्ष करने से बाज नहीं आए। इससे कूटनीति के प्रति उनकी खोखली सोच और राजनीतिक अपरिपक्वता का ही परिचय मिला। पता नहीं कैसे वह यह भूल गए कि डोकलाम विवाद के वक्त उन्होंने चीनी राजदूत से मुलाकात कर अपनी किरकिरी कराई थी? कांग्रेस को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि चीन की ओर से मिल रही चुनौती के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद से पूर्वोत्तर के विकास के प्रति विशेष ध्यान दिया है। पूर्वोत्तर के राज्य न केवल शेष देश से कटे-कटे से रहे हैं, बल्कि विकास में भी पिछड़ गए हैं। मोदी सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इसका उसे राजनीतिक फायदा भी मिला है। आज पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकार है।

चीन केवल अरुणाचल पर ही नजरें नहीं गड़ाए, वह पूर्वोत्तर के कुछ अन्य क्षेत्रों को लेकर भी विवाद उत्पन्न करता रहा है। भारत को परेशान करने के लिए वह कभी ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का सहारा लेता है तो कभी सिक्किम के नाथू ला दर्रे पर समस्याएं खड़ी करता है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि भारत सरकार पूर्वोत्तर के विकास के साथ उसकी सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दे। चूंकि आज के युग में सैन्य टकराव कोई विकल्प नहीं इसलिए इसका औचित्य नहीं कि भारत और चीन सेना के जरिये किसी विवाद का समाधान करने के बारे में सोचें। चीन एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरने के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि भारत अब 1962 जैसी स्थिति में नहीं। विडंबना यह है कि इसके बावजूद वहां के मीडिया का एक हिस्सा उकसावे वाली बातें करता रहता है। उसे पता होना चाहिए कि छोटा सा भी सैन्य टकराव आर्थिक-व्यापारिक रिश्तों पर गहरा असर डालेगा। इसके चलते चीन के विश्व महाशक्ति बनने के सपने को धक्का पहुंच सकता है। आज चीन के पास भारत जैसा विशाल बाजार और कोई नहीं और यह किसी से छिपा नहीं कि अमेरिका के साथ व्यापार संघर्ष ने उसकी समस्याएं बढ़ा दी हैं। चीन इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि भारत के साथ व्यापार संतुलन कुल मिलाकर उसके ही पक्ष में है। चीन को होने वाला भारत का निर्यात बहुत ज्यादा नहीं। दरअसल भारत के पास कृषि उत्पादों के अलावा ऐसा बहुत कुछ है भी नहीं जो चीन को निर्यात किया जा सके और चीन अपना कृषि बाजार खोलने के लिए तैयार नहीं है। इसके विपरीत चीन बड़े पैमाने पर भारत में बुनियादी ढांचे में निवेश करने का इच्छुक है। उसकी यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब रिश्ते सामान्य बने रहें और वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करना छोड़े। चीन की रणनीति अक्सर हठधर्मिता वाली होती है और वह जब भी ऐसे रवैये का परिचय देता है, संबंध सुधार में बाधा आती है और अविश्वास बढ़ता है। उम्मीद है कि वुहान शिखर वार्ता के बाद चीनी नेतृत्व को यह समझने में आसानी हुई होगी कि भारत से बेहतर संबंध उसके अपने हित में हैं।

response@jagran.com

कल भारत खुला है या बंद

हास्य-व्यंग्य

ज्ञान चतुर्वेदी

बंद के लिए शिकायत दर्ज कराने का अब एक ही तरीका शेष है कि शिकायत के नाम पर एक दिन का भारत बंद करा दिया जाए

ब्रेकिंग न्यूज है कि कल भारत खुला मिलेगा। क्या आपको भी यह पता था कि कल भारत खुला हुआ है? मुझे तो नहीं पता था। मैं मान रहा था कि जब रोज ही भारत किसी न किसी कारण से बंद रहता है तो कल भी बंद ही रहेगा, पर भाग्य का खेल है कि कल खुला मिल जाएगा। भारत आजकल इतनी बार बंद होता है कि अब यह खबर अफवाह जैसी लगती है कि भारत कल बंद नहीं रहेगा। किस्मत का करिश्मा ही कहिए कि भारत कल खुला है।

भारत बंद का आह्वान आजकल कोई भी दे डालता है। भारत भी विरोध नहीं करता। तुरंत बंद हो जाता है। मानों, बंद होने को तैयार बैठा हो। भारत अब अपनी दुकान का शटर, खुलने वाले दिनों में भी आधा गिराकर ही रखता है-कोई आह्वान करे तो खटाक से बाकी का भी खींचकर बंद करने की सुविधा रहेगी। तभी तो भारत का खुला होना अब एक घटना है और बंद होना बस यूं ही सी बात। खुला मिले तो विश्वास ही नहीं होता। बंद दिखे तो बड़ा सहज सा लगता है। खुला मिले तो धोखा सा लगता है। भारत बंद हो तो एक आश्वस्ति सी हो जाती है कि देश में सब ठीक चल रहा है।

खुले भारत में हमेशा यह आशंका बनी रहती है कि वह कभी भी बीच में ही बंद हो सकता है। हाल का उदाहरण लें। जिसने भी भारत खुले होने का भरोसा किया था, सब फंस गए। एंबुलेंस का कांच टूटकर उस मरीज के हाथ में धंस गया जो भारत खुला होने की खुशी में, खुले बाजार से बासी मिठाई खाकर बीमार पड़ गया था। स्कूल बस को घेरकर वे खड़े थे और अंदर बच्चे बिलख रहे थे। खुला हुआ भारत धोखा था मित्र। मानों किसी ने खुले का लालच देकर भारत बंद में फंसाने के लिये सारा स्वांग रचा हो। तुम भारत को खुला मानकर घर से निकलते हो और उनके जाल में फंस जाते हो। हर खुला रास्ता कभी भी बंद हो सकता है। भारत खुला भी हो तो बंद टाइप लगता है। जब तक कोई ऑफिशियली न बता दे आप विश्वासपूर्वक बता नहीं पाते कि भारत खुला ही है, क्योंकि बंद तो बंद लगता ही है, खुला भारत भी कमोबेश बंद जैसा ही रहता है। वह खुले वाला खुलापन खोजे नहीं मिलता। खुले में बंद रहना सीख गया है भारत। लगता है कि उसे भी मजा आने लगा है बंद रहने में। खुले होने को भूलता जा रहा है देश। भारत का खुला होना अब एक पॉजीटिव न्यूज की तरह छापा जा सकता है। रोज की बात को कोई कब तक छापे।

कल भारत खुला है, यह आज की सूचना है, पर हमारी सलाह है कि कल सुबह एक बार फिर से पता करके ही बच्चों को स्कूल के लिए निकालना। सुबह की न्यूज देख लेना। यहां वहां से कंफर्म कर लेना। हो सकता है कि देर रात किसी ने भारत बंद करवाने की ठानी हो। रातें बड़ी लंबी होने लगी है आजकल। रातों में रोशनी बढ़ा दी गई है, परंतु पहले से ज्यादा अंधकार रहने लगा है देश में। एक धुकधुकी सी लगी रहती है भारत को, रात भर कि कल सुबह में खुला पाऊंगा या नहीं?

इस चिंता में ठीक से सो ही नहीं पाता भारत। सुबह सब ठीक भी मिले तो भी डरते रहते ही घर से निकलता है भारत। भारत खुला भी हो तो भी वह बार-बार चौंक सा जाता है। वह आशंकित होकर, बीच-बीच में सब तरफ गर्दन घुमाकर देखता रहता है। उसे पता है। लंबा अनुभव है उसका। कोई रोकेगा नहीं उनको। बंद कराने वाले यहां किसी भी दिशा से आ सकते हैं। वे किसी भी टोपी, गमछा, दाढ़ी, डंडे, नारे, विश्वास, अंधविश्वास, राजनीति, धर्म, जाति, संप्रदाय, लाठी, भाला, बल्लम या बंदूक के साथ आ सकते हैं। भारत खुला हो तब भी बंद की आशंका से डरा डरा रहता है। हर पल इस चिंता में रहता है कि कहीं कोई किसी बात का बुरा मानकर उसे बंद कराने न पहुंच जाए।

लगातार भारत बंद के चक्कर में बड़े काम निलंबित हैं, परंतु वह किसी से शिकायत नहीं करता। वैसे भी, कोई किससे शिकायत करे? जहां शिकायत दर्ज होनी थी वह जगह भारत बंद के कारण बंद पड़ी है। भारत के लिए शिकायत दर्ज कराने का अब एक ही तरीका शेष है कि वह भी इस शिकायत के नाम पर एक दिन का भारत बंद करा दे। भारत बंद करा दो तो कोई शिकायत नहीं करता। बस, भारत बंद ठीक से गुजर जाए, यह चाहता है भारत। भारत बंद के दौरान किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला तो देश में उत्सव सा मनता है। अब भारत बंद स्वयं कोई अप्रिय घटना नहीं मानी जाती।

कल भारत खुला है और मुझे कल ही सारे निलंबित काम निबटाने है। परसों का कोई भरोसा नहीं। परसों वह खुला रहेगा कि बंद, कौन कह सकता है? इतने मुद्दे देश के समक्ष खड़े है जिन्हें बंद द्वारा सुलझाना है। इतनी बसें जलने को लालायित हैं। इतने बयान जारी होने को बेचैन हैं। इतने नारे और मुट्ठियां तत्पर हैं। जब इतना है तो परसों की कोई कैसे कहे? कल भारत खुला है, जो करना है कल ही कर लें। फिर कहीं ऐसा न हो वक्त की करवट के साथ भारत खुलने से पहले ही बंद हो जाए। इसलिए समय रहते अपने काम निपटा लें।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | कंपनियों का पंजीकरण

स्रोत : कंपनी मामलों का मंत्रालय

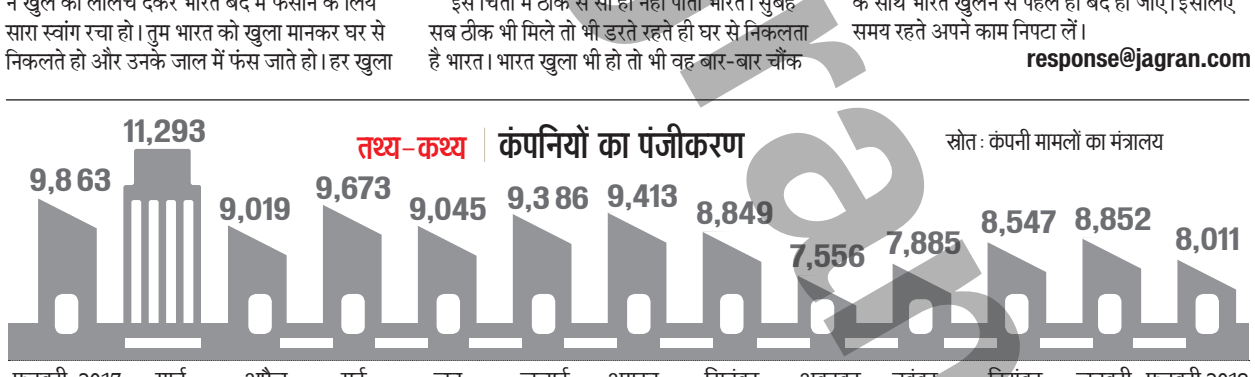

ऊर्जा

स्वयं पर जीत

सृष्टि के आरंभ काल से ही प्रत्येक जीव में दूसरों पर शासन करने और दूसरे को जीतने की आकांक्षा पाई जाती है। संभवतः सत्ता आदमी की मूल प्रवृत्ति है। दूसरों को जीतने की इस कामना के चलते ही सर्वदा से युद्ध होते आए हैं। प्रारंभ में एक कबीला दूसरे कबीले पर, एक राज्य दूसरे राज्य पर और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अधिकार करने और उसे जीतने का उपक्रम करता रहा है। हम दूसरों को जय करने से पूर्व यदि खुद को जय कर लें तो सारे विवाद, लड़ाई-झगड़े स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। खुद को जीतने का अर्थ है, खुद पर नियंत्रण, लेकिन यह इतना सरल नहीं है, पर यह कार्य साधना के जरिये आसानी से हो सकता है।

भारतीय दर्शन में मन की चंचलता पर विपुल सामग्री उपलब्ध है और इसको साधने के उपायों पर भी बहुत कुछ कहा गया है। देखा जाए, तो गीता में श्रीकृष्ण इसी मन को साधने के लिए सखा अर्जुन से अनेक उपायों की चर्चा करते हैं। हमारा मन कभी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं रहता कि कोई हम पर शासन करे या अधिकार जताए। दरअसल इसे नकारने में यह भावना अधिक काम करती है कि कोई नहीं चाहता कि कोई उस पर शासन चलाए। संयुक्त परिवारों की धारणा अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। कुछ तो परिस्थितियां बदली हैं और कुछ लोगों की चेतना में भी परिवर्तन हुआ है। शायद इसी से एकल परिवारों को लोग कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं। इसके पीछे आर्थिक कारण भले ही एक महत्वपूर्ण तथ्य हों, लेकिन स्वतंत्रतापूर्वक रहने और कोई हम पर अधिकार न चलाए, यह भावना भी काम करती है। इस समस्या के कारण इन दिनों परिवार में माता-पिता उपेक्षित हो रहे हैं।

अब यहां पर फिर मन को साधने के लिए गीता की शरण में जाने की जरूरत महसूस होने लगती है। सारे झगड़ों के मूल में यह मन ही है, जो हमें स्वतंत्रतापूर्वक जीने का पाठ पढ़ाता रहता है। इसी के कारण हम किसी के शासन में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि किसी का नियंत्रण या मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, किसी पर शासन न चलाएं और सभी को, परिवार से लेकर राष्ट्र तक अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आगे बढ़ने दें।

डॉ. विश्राम

सिग्नल सिग्नल

मोबाइल सिग्नल के खेल ने अच्छों अच्छों को परेशान कर रखा है। पर हैरत तब हुई जब यह संबंधित मंत्री को भी गच्चा दे गया। दरअसल, दूरसंचार मंत्री हाल में अरुणाचल प्रदेश गए थे। वहां मंत्रियों की बैठक थी और कुछ नए टावर भी लगाए गए थे ताकि प्रदेश की जनता को फोन पर परेशानी न आए। बताते हैं कि जब मंत्री जी ने टावर का प्रभाव दिखाने के लिए फोन लगाया तो वहां चीन की कंपनी का सिग्नल आ रहा था। थोड़े आगे पीछे हुए तभी भारतीय कंपनी का सिग्नल आया और बात हो पाई।

झंडे गाड़कर जा रहे हैं

लुटियंस जोन में बैठने वाले सरकारी बाबुओं के तरह-तरह के किस्से मशहूर हैं। बताया जाता है कि एक सचिव स्तर के अधिकारी जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, वह जब नौकरी पर आए थे तो उनकी विदेश घूमने की बड़ी इच्छा थी। जब ऊंचे ओहदे पर पहुंचे तो अक्सर विदेश-जाने लगे, लेकिन काम का बोझ इतना ज्यादा था कि परेशान हो गए। कहने लगे कि जब सचिव बन जाएंगे तो विदेश दौरे पर काम कुछ नहीं होगा बस मेज पर झंडे लगाकर दस्तखत कर फोटो खिचवाएंगे। यह बात अलग है कि जब ये साहब सचिव बन गए तो काम और बढ़ गया। बहरहाल उन्होंने सचिव बनकर जो काम किया है, वैसा उनसे पहले कोई नहीं कर पाया है। उन्होंने टारगेट हासिल करने का कीर्तिमान ही बना दिया। यही वजह है कि आजकल उनके सहयोगी उनसे चुटकी लेते हैं कि कोई बात नहीं मेज पर झंडे लगाकर फोटो भले ही न खिंचवाई हो, लेकिन आप झंडे गाड़कर जरूर जा रहे हैं।

राजरंग

बदला चरित्र

पीएम मोदी की वुहान (चीन) में राष्ट्रपति जिनफिंग से होने वाली मुलाकात को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों में जबरदस्त अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन इस माहौल में कुछ ऐसा भी होता रहा है जो बहुत ही दिलचस्पी भरा था और दोनों देशों के चरित्र से भी मेल नहीं खाता। मसलन, मोदी की यात्रा की आला अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी दी, लेकिन सख्त निर्देश दिया कि जानकारी कैसे मिली है इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। लेकिन मीडिया के लोग हैरान हो गए जब उसी दिन बीजिंग में चीन के उप-विदेश मंत्री ने आधिकारिक तौर पर मोदी की यात्रा व राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात का एजेंडा बताया। चीन की तरफ से आधिकारिक तौर पर दी गई और भारत की तरफ से दी गई गैर-आधिकारिक सूचनाओं में कोई अंतर नहीं था। एक ही बात दोनों पक्षों की तरफ से बताई गई, लेकिन बताने का तरीका अलग रहा। एक तरह से देखा जाए तो भारत ने चीन जैसा व्यवहार किया जबकि चीन ने भारत जैसा।

मन भर गया

हाल में कांग्रेस नेता और अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने दो बार अपनी पार्टी को असहज कर दिया। पहले तो मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कांग्रेस नेतृत्व द्वारा की गई महाभियोग की तैयारी का विरोध कर दिया। और तीन दिन पहले यह कहकर सनसनी फैला दी कि कांग्रेस के हाथ पर अल्पसंख्यकों के खून के धब्बे हैं। अब यह तो नागवार गुजरना ही था। कांग्रेस की मुश्किल तो दोहरी थी। सीधे कार्रवाई करें या उन्हें भला बुरा करें तो यह माना जाता कि अल्पसंख्यक नेता ठहरे सो कार्रवाई कर दी। न करें तो मुश्किल कि न जाने फिर कब कोई नया राग छेड़ दें? पर उससे बड़ा सवाल जो कांग्रेस को सता रहा है वह यह है कि खुर्शीद साहब का मन राजनीति से भर गया है या फिर कांग्रेस से? आखिर उन्हें भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल पता है।

ट्वीट-ट्वीट

बढ़ा-चढ़ाकर की जाने वाली तमाम बातों के बावजूद मोदी-चिनफिंग वार्ता से बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है। भारतीय विदेश सचिव ने उपलब्धियों का जो पुलिंदा पेश किया है उसमें ठोस चीजें नहीं हैं। उम्मीद करें कि भारत आंख मूंदकर चीन के बहकावे में नहीं आएगा।

ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

देश के महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को बचाने के लिए नीलामी के जरिये उन्हें कारोबारी घरानों को सौंपने के अलावा कुछ और भी विकल्प तलाशे जाने चाहिए।

विलियम डेलरिंपल@DalrympleWill

अगर आप घर की सफाई के लिए किसी की सेवाएं ले रहे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप अपना घर उन्हें बेच रहे हैं। कोई लाल किले को नहीं बेच रहा है। यह सरकारी धन को बचाने और विरासत स्थल को संवारने का खास तरीका है।

चेतन भगत@chetan_bhagat

मौजूदा कानून के मुताबिक न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की संस्तुति निर्णायक एवं बाध्यकारी है। ऐसे में क्या मोदी सरकार कानून से ऊपर है?

पी चिदंबरम@PChidambaram_IN

जनपथ

उत्तर-दक्षिण कोरिया पुन : आ रहे साथ,
मोदी-चिनफिंग भी इधर मिला रहे हैं हाथ।
मिला रहे हैं हाथ देखती दुनिया सारी,
एटम बम पर शांति पड़ रही देखो भारी।
इधर बिताए साल लड़ाई करते सत्तर,
रिश्ते अब भी पाक संग हैं दक्षिण-उत्तर।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 28 अंक 284**